MATTER RAISED WITH PERMISSION OF THE CHAIR

Truckers' Strike

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Madam, for the last nine days, the truckers' strike is going on. It is shocking that Government is still not at all able to solve the problem. In fact, as per the estimates, the nation is losing about one thousand crore of rupees per day due to this.

In the country, small-scale industries, cotiage inaustnes and poultry industries have come to standstill, besides big industries. If it continues, the total life is going to be paralysed. Diesel is not coming; supply of petrol may also be stopped. *...{Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You have made your mention. ... *...interruptions)...*

DR. T. SUBBARAMI REDDY: No. Now, I want to know till today, what efforts the Government have made. Only one meeting has taken place between the Minister of Surface Transport and the truck associations. ... *...{Interruptions)...*

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradehs) : This is a very serious issue ....*{Interruptions)...*

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Till today, why is the Government so quiet? I want an assurance from the Government. ... *{Interruptions)...*.If it continues, there is going to be a chaos in the country. *...{Interruptions)...*So many drivers are actually losing their livelihood. Some people have died because of the poverty problem. *...{Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu) : In Tamil Nadu, powerloom sector is also suffering. *...{Interruptbns)...*

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) **:** मैडम, ट्रक हड़ताल की वजह से भी यातायात व्यवस्था बंद पड़ी हैं बल्कि लोगों का सामान गंतव्य स्थानों पर समय पर नहीं पहुंच पा रहा है और उनको बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है। सरकार समय रहते इस संबंध में पहल करे और वक्तव्य दे कि आखिर क्या वजह हैं कि वह उनके साथ ऐसा बरताव कर रही है और इस मामले में पहल नहीं हो पा रही हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश) **:** मैडम, इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है । यह जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए । ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Manmohan Singh wants to say something.

DR. MANMOHAN SINGH (Assam): All that we know about the truckers' strike is that a number of advertisements have appeared in the newspapers on behalf of the Government. I say it with all humility that, at least, in some of the cases, the Government's stand appears to be not well-explained. Therefore, it is very important that a matter, which affects so vitally the economy of our country, should be discussed. Transport is an important link in the economic management of our country. This is the eighth day of the strike. The strike is going on. There is no end to this strike in sight. It is absolutely important that the Government should come to the House to tell us what they propose to do to handle this strike.

THE DEPUTY CHAIRMAN: She wants *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: In Tamil Nadu and other places, powerloom sector is also suffering. *...l/nterruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: She is replying.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Let me respond to this. उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगी कि ट्रक हड़ताल के विषय मे कल ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुओ-मोटों स्टेटमेंट सदन में देंगे ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.00 p.m. for lunch. At 2.00 p.m., we will discuss Ministry of Agriculture to be initiated by Shri Rama Shanker Kaushik.

The House then adjourned for lunch at fifty eight minutes past twelve of the clock

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE

MR. CHAIRMAN: Shri Rama Shanker Kaushik.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि कृषि मंत्रालय के कार्यकरण पर, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का मुझे अवसर मिला । श्रीमन्, हमारे देश में हमारी आर्थिक व्यवस्था के मामले में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है और सदियों से हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है । हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारा रहन-सहन, हमारी विचार शैली-इन सबका ताल्लुक कृषि से रहा हैं । लेकिन आज हमारे देश में कृषि के संबंध में जो स्थिति है, वह बहुत ही दुखद होती चली जा रही है । महोदय, कृषि मंत्रालय का कार्य है कि कृषि की उपज को बढ़ाए। दूसरा है कि जो कृषक हैं, जो खेती पर निर्भर हैं, उनकी उपज को उनको लाभप्रद मूल्य मिले और तीसरा उनकी माली हैसियत बढ़े हैं । लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि कृषि मंत्रालय के द्वारा इन तीनों ही बातों में पूरी तरह से उपेक्षा बरती गयी हैं । हम यह मानकर चलते थे, योजना आयोग यह मानकर चलता हैं कि अगर हमें अपनी विकास दर को बढ़ाना रहेगा। यह केवल कहने की ही बात नहीं है, पिछला अनुभव भी यह बताता है कि जब जब कृषि की विकास दर बढ़ी है, तब तब हमारे सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर भी बढ़ी हैं । हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यह तकादा अवश्य करती हैं कि हमारी कृषि की विकास दर बढ़नी चाहिए । वैसे, कृषि मंत्रालय ही नहीं, हर मंत्रालय एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है । किसी भी एक मंत्रालय को हम यह नहीं कह सकते कि वह निरपेक्ष हैं । जिंदगी के अन्य सारे पहलू जैसे एक-दूसरे से जुडे हुए रहते हैं , उसी प्रकार से हर मंत्रालय एक-दूसरे से जुडा हुआ है, लेकिन जहां तक कृषि मंत्रालय का सवाल है, वह तो अनेक विभागों से बहुत ही निकटता के साथ जुड़ा हुआ है । वह रासयनिक मंत्रालय के साथ पूरे तरीके से जुडा हुआ है, उद्योग मंत्रालय के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है । वाणिज्य मंत्रालय से उसका रिश्ता अब और गहरा होता चला जा रहा है, वह पहले भी था लेकिन हमारी उदारीकरण और आयात-निर्यात की नीति के कारण वह आज भी गहरा हो गया है । लेकिन यह भी एक हकीकत है कि कृषि मंत्रालय की आवाज इन मंत्रालयों में बहुत ही कम है जिसकी वजह से कृषकों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता हैं । कृषि मंत्रालय को भी जो उनके लक्ष्य हैं, उनका जो मकसद हैं, उसे हासिल करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसलिए पहली मांग तो श्रीमन्, मैं आपकी मार्फत से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय में कुछ ऐसी शक्ति निहित की जानी चाहिए जिससे कृषकों की भलाई के लिए और हमारी कृषि की विकास दर को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय दूसरे विभागों मे दखल दे सके । हम देखते हैं कि गन्ना कृषि मंत्रालय का विषय हैं लेकिन चीनी की नीति विभाग बनाता हैं। इसी प्रकार से और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें दाम तय किए जाते हैं – चाहें गन्ने की कीमतों के मामले में हो या जो सपोटिंग प्राइस होता है, उसके मामले में हो – उसमें भी कृषि मंत्रालय की आवाज वैसी नहीं है जैसी होनी